I submit that we are establishing a good institution. But it must be seen that the Lokpal is not influenced by the ruling party. That is a very important point.

MR. CHAIRMAN : The Minister will reply tomorrow.

---

**16.34 hrs.**

## HALF-AN-HOUR DISCUSSION

### Farmers' dues Outstanding Against Sugar Mills in U. P.

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** (हापुड़) : सभापति महोदय, आधे घन्टे की जिस चर्चा के माध्यम से मैं जिस चर्चा को उठाने जा रहा हूं, उसका सम्बन्ध उत्तर प्रदेश के उन किसानों से है जिन का करोड़ों रुपया आज चीनी मिल मालिकों की ओर शेष है।

**16.34½ hrs.**

[Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

लेकिन उसकी चर्चा प्रारम्भ करने से पहले मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके विभाग की ओर से उनको किस तरह से अन्धकार में रखा जाता है, इसको वह देखें। प्रश्न में बड़े स्पष्ट रूप से पूछा गया था कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ चीनी मिलों द्वारा अब भी किसानों की बहुत सी राशियों का भुगतान किया जाना शेष है ? इसका जो उत्तर विभाग ने तैयार करके मन्त्री महोदय को दिया है और जिसको मन्त्री महोदय ने इस सदन में प्रस्तुत किया है उसमें लिखा है कि 1968-69 के मौसम का 31 मई, 1969 को गन्ने की कीमत की बकाया राशि का एक विवरण दिया जा रहा है। मेरा स्पष्ट अभिप्राय यह था कि इस समय उन किसानों का कितना पैसा मिल मालिकों की ओर शेष है। उसकी जानकारी विभाग की ओर से, मन्त्री महोदय की ओर से सदन को नहीं दी गई। पूरी जानकारी न दे कर केवल एक मौसम के आंकड़े उन्होने दे दिये हैं। ऐसा करके पिछला पैसा जो इन मिलों की ओर से शेष था उसको छिपाने का यत्न किया गया है ताकि कोई बहुत बड़ी राशि हो कर उत्तर प्रदेश के किसानों में और सदन के सदस्यों में भी असन्तोष वह पैदा न कर दे।

एक वर्ष की राशि का जो विवरण दिया गया है उससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के किसानों का चीनी मिल मालिकों की ओर 8 करोड़ 65 लाख 45 हजार रुपये शेष था और जो सैस का पैसा (गन्ना उपकर का पैसा) बकाया था वह करीब 4 करोड़ 26 लाख 63 हजार था। यह उपकर इस वास्ते वसूल किया जाता है ताकि सरकार गन्ने की नस्ल को सुधार सके। गन्ने में कोई कीड़ा लगे तो उससे किसानों की फसल को बचाया सके या और इसी प्रकार के और काम कर सके। गत वर्षों के सम्बन्ध में इस में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मैंने कृषि राज्य मन्त्री श्री शिंदे को एक पत्र लिख कर पूछा था कि आपके पास कोई जानकारी है ? कृषि राज्य मन्त्री को जो जानकारी उत्तर प्रदेश की सरकार से मिली उसको उन्होंने बड़ी कृपा करके मेरे पास भेज दिया। वह राशि भी करीब चालीस लाख की है। मैं समझता हूँ कि यह राशि सत्य से कोसों दूर है। फिर भी अगर मैं इस राशि को सत्य मान भी लूं तो करीब चौदह करोड़ रुपया इस प्रकार का है जो उत्तर प्रदेश के किसानों का चीनी मिलों की ओर बकाया है जब एक प्रान्त के किसानों का इतना पैसा चीनी मिल मालिकों की ओर बकाया है तो हिसाब लगाया जाए सारे देश का, जहां-जहां चीनी मिलें हैं और जहां-जहां गन्ना पैदा होता है कितना पैसा किसानों का उनकी ओर बकाया है ? उत्तर प्रदेश का किसान अपने अधिकारों के लिए थोड़ा बहुत जागरूक हो गया है। लेकिन फिर भी जब उसका इतना पैसा बकाया है तो बिहार जैसे राज्य में किसानों का कितना पैसा चीनी मिल मालिकों की ओर बकाया होगा ? इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। पांच सात राज्य जहाँ चीनी मिलें हैं और जहां के किसान गन्ना पैदा करते हैं, उन सब का हिसाब लगाया जाय तो करीब

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

आधा अरब रुपया इस प्रकार का होगा। जो चीनी मिलों की ओर किसानों का बकाया होगा। इस रुपये को वे इस वास्ते अपने पास रखे हुए हैं कि उस रुपये से वे अपने दूसरे व्यापार करें।

सरकार देखे कि इसका परिणाम क्या हो रहा है। किसान को जब समय पर पैसा नहीं मिलता है तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरह से कर सकता है। गन्ने की फसल को सुधार वह नहीं कर पाता, खाद समय पर नहीं खरीद पाता, अच्छा बीज नहीं खरीद पाता है और किसान को इससे जो प्रोत्साहन मिलना चाहिये वह सारे का सारा इस प्रकार से समाप्त हो जाता है।

एक विशेष बात मैं आप से कहना चाहता हूँ पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में जब संविद सरकार बनी थी तब उन्होंने चीनी मिल मालिकों के साथ कुछ कड़ाई बरतनी प्रारम्भ की थी। उन्होंने कहा था कि चीनी मिल चालू होने से पहले किसान का जो पैसा चीनी मिलों की ओर बकाया है, चीनी मिल मालिक अगर उस पैसे को नहीं देंगे तो इन मिलों को चीनी मिल मालिक नही चलायेंगे, गवर्नमेंट उन मिलों को चलायेगी। जब उन्होंने यह चेतावनी दी तब कुछ पैसा तो दे दिया गया लेकिन सारा पैसा नहीं मिल सका और संविद सरकार का अभियान मध्य में ही रह गया। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जितनी चीनी मिलें हैं उनको चाहे केन्द्रीय सरकार के माध्यम से इस प्रकार की एक चेतावनी जानी चाहिये कि अगली फसल चालू होने से पहले अगर किसानों का पैसा जिन मिलों की ओर बकाया है वह वापिस नहीं दिया गया तो उन मिलों को उन मिलों के मालिक नहीं चलायेंगे, सरकार स्वयं उनको चलायेगी और वे मिल मालिक उन मिलों को हाथ नहीं लगा सकेंगे।

आपको सभापति महोदय, सुन कर आश्चर्य होगा कि यह जो लिस्ट मेरे पास है इसमें मैंने पढ़ा है कि किस मिल पर कितना बकाया है उसको विस्तार से कह कर मैं ज्यादा कटुता उत्पन्न करना नहीं चाहता हूं। लेकिन दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जिन चीनी मिलों के साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं का संबंध है सबसे बड़ी धनराशियां उन मिलों की ओर ही बकाया हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको कृषि मन्त्री श्री जगजीवन राम देखें। जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, बड़े-बड़े पैसे वाले हैं उन्होंने किसानों का यह पैसा रोक कर रखा हुआ है। अगर किसानों का आधा अरब रुपया ये अपने पास रोक कर रखेंगे तो किसानों के साथ न्याय ये कर रहे हैं, यह कैसे कहा जा सकता है।

इस रुपये को दिलाने का प्रयत्न करने के बजाय उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने क्या किया इसका भी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा की कि मिल मालिकों को परचेज टैक्स के अंदर सोलह पैसे प्रति क्विंटल की छूट दी जायेगी। परचेज टैक्स माफ करने का अधिकार राज्य सरकार को हैं। उलटे मिल मालिकों को तो राज्य सरकार सुविधा देना चाहती है लेकिन किसानों का जो पैसा मिल मालिकों की ओर बकाया है, उसको राज्य सरकार दिलाना नहीं चाहती है, उसकी ओर ध्यान देना नहीं चाहती है और केन्द्रीय सरकार भी ध्यान नहीं देती है। यह सरासर अन्याय है।

पैसा जो शेष रह जाता है इसका एक और भी बहुत बड़ा कारण है। पिछली बार जब गन्ने की कीमत तय होने का सवाल यहां आया था तो कई सप्ताह लगातार उस पर चर्चा चलती रही। कृषि मन्त्री जी सभा में उपस्थित हैं। उनको स्मरण होगा कि उन्होंने सदन में खड़े होकर आश्वासन दिया था कि चीनी मिलों को कम से कम दस रुपये का भाव निश्चित रूप से किसानों को देना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा था कि जो चीनी मिलें किसानों को दस रुपये का भाव देंगी, वही सर-

कारी सुविधायें प्राप्त कर सकेंगी और दूसरी मिलें सरकारी सुविधाओं से वंचित रहेंगी । मैं श्री जगजीवन राम से यह सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या उनकी जानकारी में उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की शुगर मिलें नहीं हैं, कि जिन्होंने 7 रुपये 35 पैसे से भी कम दिया है। वह कृपा करके एक भी शुगर मिल का नाम बतायें, जिस ने गन्ने का भाव दस रुपये के कम दिया हो और सरकार ने उसके खिलाफ कार्यवाही की हो और उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित किया हो। अगर किसानों के साथ राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार न्याय नहीं कर सकेंगी, तो फिर किसान को किस तरह गन्ने और अन्य चीजों के उत्पादन में प्रोत्साहन मिलेगा ?

किसान को दिये जाने वाले पैसे के सम्बन्ध में मेरा सीधा-सादा सुझाव यह है—इसमें कनज्यूमर, मिल-मालिक या गन्ने के उत्पादक किसान को, किसी को भी, आपत्ति नहीं होगी ; मान लीजिए कि सरकार कल गन्ने का भाव साढ़े सात रुपये या दस रुपये तय करती है । जिस समय किसान अपना गन्ना ले कर चीनी मिल पर जाये, तो साढ़े सात रुपये या दस रुपये के हिसाब से तो उसको उसी समय पेमेंट कर दिया जाये बाद में चीनी मार्केट में जिस भाव पर बिके, उसमें किसान को उसके अनुपात से पैसा द दिया जाये । मुझे पता चला है कि मद्रास में डी० एम० के० सरकार ने पिछले साल इस प्रकार का परीक्षण करना चाहा था। पर मुझे जानकारी नहीं है कि उसका क्या सुपरिणाम सामने आया ।

या फिर स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई के इस सिद्धान्त पर अमल करना चाहिए कि जितने रुपये मन चीनी, उतने आने मन गन्ना । उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी । इन दोनों में से एक सिद्धान्त को स्वीकार कर के किसान के साथ इंसाफ करना चाहिए ।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसान का 14 करोड़ रुपये का बकाया है । दूसरे राज्यों में किसान को कितना रुपया बकाया है, मेरे पास उसके आंकड़े नहीं है, लेकिन इस सम्बन्ध में अनुमानित आंकड़े 50 करोड़ रुपये के हैं । वह सब पैसा शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसान के साथ देर तक बेइन्साफी न हो सके ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): I am thankful to the hon Member, Shri Prakash Vir Shastri, for raising this discussion on the floor of the House because in many states, especially in the U. P., this is an important topic of discussion in newspapers and for agitation in the field.

Before going into the facts of the case. I would submit for the information of the hon. Member as to what is the legal position, what is Government's policy approach, what is the real situation in the field. As far as the legal position is concerned, the law is very clear on this issue. There is a Sugar Cane Control Order under which the manufacturers of sugar have to pay within 14 days the price of the cane to the cane-growers. That is the legal obligation. If the price is not paid within the stipulated period, the purchaser of cane is liable for prosecution under the provisions of the Essential Commodities Act and orders thereunder. There is also a provision that the State Governments can recover these dues as arrears of land revenue.

So, as far as the legal position is concerned, it is very clear. Our policy approach in regard to this has always been—because ultimately it is the State Government which has to implement this—but our advice to the State Government has been that they should not hesitate in taking very strong steps against the factory—owners for recovering the arrears of cane price. We have been drawing their attention from time to time and even this year—this year the season ended a little later than the normal year—we have written to the State Governments and especially we have drawn the attention of the UP Government that they must see that the arrears of cane price are paid in time.

As far as the policy approach is

[Shri Annasahib Shinde]

concerned we have no reservation. And, we would like very much that whatever may be the circumstances, whatever may be the factors, under no circumstances, factory-owners should withhold the cane price to cane growers because in many of the areas of the country the cane growers are all small holders and they have no other cash crop except sugarcane and unless they receive their dues and the price of the cane in time it is very difficult for them not only to run the day-to-day agricultural activities but to plant the crops and to put the necessary inputs. Unless they get the price it is not possible for them to carry on their day-to-day agricultural activities and it is a life-and-death question to many of the small farmers engaged in this crop.

As far as the problem is concerned, we are completely aware of all these things and that is why we have been advising the State Governments that they should not hesitate to adopt some stringent measures against the factory owners.

Then, so far as the facts are concerned, in the figures given by Shastriji, there were some discrepancies in the figures -- some sets of figures were given by factory-owners and some sets of figures were given by the U. P. Government. Naturally we have to rely of the figures given by the U. P. Government. As far as the U. P. Government is concerned, the latest position is like this. On 31st May, 1969, the arrears of cane price excluding commission and cane cess were Rs 7.89 crores. By the 15th June this had come down to Rs. 5.67 crores. The latest figure with me as on 30th June shows this. As far as the current dues are concerned, the figure is Rs. 1,30,78,000 ; so the figure has come down very much.

As far as the arrears of cane purchase tax for the previous year is concerned, it is quite a large amount, it is Rs. 3.50 crores roughly. The break-up of this is like this. Under stay by court an amount of Rs. 1.11 crores remains due to some court disputes etc. and under agreement with the Government for paying in instalments would be about 21.87 lakhs. This is the position as far as U. P. is concerned. So, that figure, in the beginning would appear to be a little on the high side. But the position has now considerably improved. And, a substantial part of the payment has been made.

I would like to tell for the information of this Hon. House and Hon. Members that the total cane price as far as the cane supply by U. P. cane growers is concerned, was roughly Rs. 120 crores. There are again two sets of figures. Shastriji may again contradict me. There are one set of figures from factory and another set of figures from U. P. Government but they are substantially the same. Out of 120 crores roughly the cane price 115 crores were paid before 31st of May and the arrears were roughly 8 crores, and the arrears now have come down to 5 crores only. The figure has come down substantially. Shastriji mentioned that throughout the country almost Rs. 50 crores are in arrears. It is a little exaggerated figure. The figure as it stood on the 15th June, 1969 in all the States was Rs. 25.15 crores.

As far as Maharashtra is concerned the figure is quite large, about 8 crores. As far as Maharashtra is concerned, there has been some misunderstanding because in Maharashtra most of the factories are cooperative factories. They have a system of making the payment after the year is completed and after they sell the entire quantity of sugar. Most of the factories are owned by farmers themselves. It is not really arrears—these are only paper arrears because most of the factories deduct deposits and reserve funds out of the cane price in consultation with the cane growers and this is only a paper figure. So, conclusion should not be taken or drawn that large arrears are due and that Government are not doing anything.

As far as the U.P. Government is concerned I would like to explain a little bit. There are two sets of factories in the State. One is habitual defaulters. It is not habitual offenders, but habitual defaulters.

I think there is a class of factory-owners who deliberately try to withhold payment for the cane. That is why many State Governments have been taking very strong steps against them. Even in UP, a number of factories have been attached. I have information about 11 factories where action taken is on the following lines: mill attached and receiver appointed, immoveable property already attached for income-tax

dues ; mill has given an undertaking to pay in instalments from Jan. 1970 etc. I do not go into details for want of time. But action has been taken against the defaulting mills.

Normally in these matters, the State Governments are authorised to go into detail and find out what is the position about individual factories. Our approach in this matter is very clear. There is a peculiar position prevailing in the sugar industry where in payment to cane growers is held up after the sale takes place. As soon as the cane is sold, there is no reason why the factory-owner should not pay the amount as the sale has been completed at that point. But the tradition that has developed in this industry in this matter is that payment is withheld even after sale.

Sometime ago, our Minister, Shri Jagjivan Ram, made a statement in the House saying that we are not very satisfied with the existing arrangement and we would like the law to be amended, if necessary. We are going into this problem. We are consulting the Law Ministry in an effort to see whether the Essential Commodities Act or the Sugar Control Order can be basically amended to remedy this state of affairs. The Law Ministry has raised some objections. But we are looking into the problem.

We have every sympathy with cane-growers. I would tell Shri Shastri that we are not neglecting farmers. Their interests are uppermost in our mind. Whatever suggestions the hon. member has made, we shall pass them on to the State Governments.

I would again take the opportunity of today's discussion to say that we would request the State Governments not to hesitate to take the strongest possible measures for recovering dues of cane-growers from the mills. We ourselves are doing everything possible to advise them to see that the arrears are cleared as early as possible.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Daimond Harbour) : I very much regret to say that this Government has been a great patron of the sugar mill-owners. On the one hand, they allow partial decontrol. The consumer has had to pay a high extra profit. 70P is the cost of production in terms of the sale price and the price went up to Rs. 7 a kilo. On the other hand, the poor farmers have not been helped to get their dues from the mill-owners.

I believe there is a State Act in UP—the Minister will correct me if I am wrong—which makes it obligatory that all dues of the sugarcane producers must be paid within a fortnight, failing which interest will accrue at the rate of 9½ per cent and the State Government will be within its rights to attach the mill-owner's property for recovery of dues. Has this been used ?

In UP, we had almost uninterrupted Congress rule and then we had President's rule for some time. So the Centre had a direct hand in this affair. I am charging this Government with being 'hand in gloves' with mill-owners for the sake of promoting its political interests. It has allowed them to rob the consumer and the sugarcane grower. Thereby it has deliberately, knowingly and in a planned manner created this situation.

Under the cirumstances, may I ask the Minister to tell us correctly and truthfully in how many cases they have proceeded against the defaulting mill-owners who have deprived the poor cane growers of their dues and in how many cases such prosecutions have ended in conviction and attachment ?

We know that 12 co-operative sugar mills in Maharashtra made an excess profit of Rs. 9 crores in 9 months over last three years average. So it can only be reluctance to pay that has resulted in this situation. What action has been taken in this regard ?

**श्री शिव चन्द्र झा** (मधुबनी) : मेरा पहला सवाल है कि इन्होंने ऐसा कहा और इन्होंने भी मंजूर किया कि हालत कुछ सुधरी है लेकिन यह बात सही है कि गन्ने के किसानों को गन्ने से जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा मिला नहीं है। अभी भी वह बकाया है। अगर गन्ने के किसानों को मिल वालों ने पैसा नहीं दिया तो मैं जानना चाहता हूं कम से कम मिल को बढ़ाने में, उसको माडर्नाइज करने में उन्होंने खर्च किया या नहीं ? मतलब इसका यह है कि यू० पी० की जो शुगर मिलें है उनका कहां तक माडर्नाइजेशन हुआ है जैसे महाराष्ट्र

[श्री शिव चन्द्र झा]

में हैं या आंध्र में हैं, उनके मुकाबले में और यदि नहीं किया है तो उसके लिए यह मिलें कौन सा कदम उठाने जा रही हैं ?

फिर जो कुछ भी पैसा किसानों को देना है और जो उस केन सेस से मिलो को करना चाहिए उसमें केन वेराइटीज में कौन कौन सी रिसर्च उन्होंने की है या कौन सी तरक्की हुई है इन मिलों के जरिये।

तीसरा सवाल यह है कि आपने आल इंडिया फीगर दिया 25 करोड़, इन्होंने 50 करोड़ कहा तो खास कर के मैं बिहार का जानना चाहता हूं, सेस को ले कर के और किसानों का, यह दोनों मिला कर कितने पैसे बाकी हैं ?

आखिरी सवाल यह है कि क्या आप यह नहीं समझते हैं यह सब जो खराबियां हैं इन सभी के निराकरण के लिए तमाम शुगर मिलें हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय करण में आ जायें ? उनका राष्ट्रीय करण हो, यह कदम सरकार कब उठाने जा रही है ?

**श्री रणधीर सिंह** (रोहतक) चेयरमैन महोदय, यह अजीब बात है कि जिसको कर्ज देना चाहिए सर्मायेदारों की तरफ से या सरकार की तरफ से, किसानों को कर्ज मिलना चाहिए लेकिन किसान का कर्ज सरकार की तरफ और मिलों की तरफ बाकी है, यह उलटा रिवाज है और बड़े अफसोस की बात है। बात है। जो किसान गन्ना बोता है उसकी वह बेहतरीन जमीन होती है, उस जमीन पर साल में एक वह फसल लेता है फिर इतना उसका प्रोडक्शन पर खर्च होना है कि मेरे ख्याल में किसी जायदाद पर, किसी जिन्स पर किसान का इतना खर्च नहीं होता है जो गन्ने पर होता है। और फिर उसके बाद जब उनको वह ले जाये मिलों में तो उसके पैसे न मिलें, उसके पैसे से सर्मायेदार सट्टे चलायें, अपनी शेयर्स में इस्तेमाल करें और ब्लैकमार्केटिंग करें, तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस किस्म के आदमियों को क्या ब्लैक लिस्ट करेगी ? ब्लैक-लिस्ट करके उन पर इतना दबाव डाले कि जितना रुपया किसान का बाकी है उसका डबुल वह तावान वह अदा करें। चाहिए तो 11 गुना लेकिन कम से कम उतना तो तावान वह दे ही। अगर न दें तो उनको ब्लैकलिस्ट करें और उनको नेशनलाइज करें, यह आप करने के लिए तैयार हैं ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों के अन्दर इस किस्म का कान्फीडेन्स हो गया है कि आप मुकर्रर करते हैं कोई कीमत जैसे यहां से 10 रुपए मुकर्रर कर दिया और आप की मानता कोई नहीं, स्टेट की सरकार नहीं मानती और कोआपरेटिव वाले भी नहीं मानते यहां से रेट चलता है श्री जगजीवन राम जी के यहाँ से 10 रुपए का और वह 7 रु० भी नहीं देते, तो जब वह आपकी बात नहीं मानते तो आपका क्या इलाज कर रहे हैं ? आप उनकी गर्दन पकड़िये और कीमत दिलवाइये। अगर नहीं दिलवाते हैं तो क्या किसान जस्टीफाइड नहीं है कि वह गन्ने की काश्त को कम करे ? अगर वह गन्ने की काश्त को कम करेगा तो क्या देश का नुकसान नहीं होगा ? ऐसी हालत में मैं पूछना चाहता हूं कि जब किसान का कान्फीडेन्श हिल गया है, आप कीमत ठीक नहीं दिला रहे तो उसके लिए क्या स्टेप आप लेने जा रहे हैं कि देश में गन्ने का प्रोडक्शन कम न हो, ठीक प्राइस मिले ?

आखिरी बात यह पूछना चाहता हूं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और इस तरह के डिफाल्टर्स के केसेज कम हों, 50 करोड़ की जगह पर अगले साल एक अरब रुपए का घाटा न पड़ जाये उससे किसानों को बचाने के लिए आप क्या स्टेप्स उठा रहे ?

18 hrs.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I will ask only one question. After the

nationalisation of major banks, the cost of sugar in the open market has come down. And there is a feeling in the country that because they behaved shabbily, the sugar industry will be nationalised and that the sugar trade will be nationalised. That is a good sign for which I congratulate the Government.

Now, I would like to know from the hon. Minister, since many mills in Uttar Pradesh have been attched because they had defaulted, whether they will take a decision here and now, without consulting the Uttar Pradesh Government and its Chief Minister —(*Interruption*)—whether they are in a position to take a decision here and now that sugar mills will be nationalised not only in Uttar Pradesh but in the whole country in the larger interests of the nation.

**श्री मोलहू प्रसाद** (बांसगांव) : सभापति महोदय, एक छोटा सा सवाल मुझे करना है ।

MR. CHAIRMAN : I am sorry. There are so many other hon. Members. It is not only one Member. If it was only one Member, I could have allowed it. But there are other Members also, and in a half-an-hour discussion, you know the procedure.

**श्री मोलहू प्रसाद** : एक छोटा सा सवाल है ।

MR. CHAIRMAN : Order, order. I cannot discriminate between one Member and another Member. I did not allow Shri Pandey also, to ask a question. I am sorry.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Mr. Chairman, Sir, Shri Jyotirmoy Basu unfortunately always introduces an element of politics in all such matters. I would only appeal to him ; sometimes back there was the United Front Government in Uttar Pradesh, and Shri Jharkande Rai, one of his colleagues, was a member of the Cabinet. I would like to know from him why at that time, when the Centre was pressing the Uttar Pradesh Government that all the previous arrears of cane price should be realised, all those previous arrears were not erased. (*Interruption*.)

SHRI S. M. BANERJEE : He comes from my group. I know he was trying to do it, but thanks to Shri Charan Singh, it was not allowed.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : All of you, together !

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : चरणसिंह जी ने शुगर मिलों को, जबतक पैसा वसूल नहीं हो गया, चलने नहीं दिया ।

SHRI JYOTIRMOY BASU : They tried and that is why they had to quit.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Obviously there were some difficulties then in the way of the United Front Government, but Shri Prakash Vir Shastri is right : Charan Singh did try his level best to see that the arrears were realised but despite that, some arrears remained. My submission is, obviously there were some difficulties. So, why should one unnecessarily make a charge against persons who are not here to defend themselves ?

SHRI JYOTIRMOY BASU : Shri C. B. Gupta's patrons would not pay.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I would assure Shri Jyotirmoy Basu that our approach is, we have no two opinions on this : the cane arrears must be realised and must be paid. On that we have no two opinions in this House.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Sir, my question has not been answered. I seek your protection. I want to know from the hon. Minister, in how many cases they wanted to proceed against the defaulting sugar mill-owners ; in how many cases they actually launched prosecution ; and in how many cases conviction and attachment orders were received. I have put three questions.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I have a list ; of course I cannot go into details because this is not a full-fledged debate...... (*Interruption*.)

SHRI JYOTIRMOY BASU : Kindly lay it on the Table.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : As I have already mentioned, against about 11 factories action has been taken by the UP

[Shri Annasahib Shinde]

Government and in regard to others they are considering the individual cases.

SHRI JYOTIRMOY BASU: This is where the trouble starts in this House. We try to put specific questions and the Treasury Benches people always try to give evasive and misleading replies. I have asked specific questions and he should have come equipped with replies to them. I am quite sure, he is equipped with them. I had asked: (a) in how many cases they wanted to proceed; (b) in how many cases they actually proceeded...... (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN: He is trying to answer your question. Please give him some opportunity to do so.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: Since this question mainly related to arrears in UP, I have got the information from UP. As I have submitted, action has been taken against 11 mills and State Government is going into the individual cases of other factories.

SHRI JYOTIRMOY BASU: That is not the reply.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: Then, Shri Jyotirmoy Basu made a very serious charge against co-operatives in Maharashtra.

SHRI JYOTIRMOY BASU: No charge. I only said that the appearance of prosperity has come about due to partial decontrol of sugar.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I wish sometimes he accompanies me to Maharashtra.

SHRI JYOTIRMOY BASU: I would if you book a seat in the plane tomorrow. I am willing.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: They are all co-operatives of farmers. Why should he have a grievance because they have got some profit?

SHRI JYOTIRMOY BASU: You have forgotten the consumer.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: Shri Shiva Chandra Jha raised two very basic points which are now and then referred to on the floor of the House. One is the problem of modernisation. In fact, as far as sugar factories in the North Indian States are concerned, modernisation is a very important problem and unless the sugar factories are modernised there will be many difficulties. Already the sugar industry is in a crisis because of low yields and low recovery. A number of steps are being taken but the factories themselves should come forward to raise resources for modernisation. They are not coming forward; they are looking to the Government to make resources or funds available to them. But the Government can only ask the financial institutions to help them and to advance loans to them. They themselves must take the responsibility because Government cannot take the entire responsibility of a mill's expansion or modernisation.

SHRI YOGENDRA SHARMA (Begusarai): Why do you not take them over?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: We have no objection if the State Governments in their judgment think that they would like to take over the mills which are not running well.

SHRI S. M. BANERJEE: If the State Government object, take over the State Governments also (*Interruption*)

SHRI ANNASAHIB SHINDE: Nationalisation is a much bigger issue. I have all my sympathy with friends opposite, but if old junks are taken over by State Governments, I do not think it will make a difference. The problem of the sugar industry is much deeper and this may not be the right solution.

MR. CHAIRMAN: You are going much beyond the scope of the debate.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I think so. I am thankful to you for drawing attention to that.

श्री शिव चन्द्र झा : आपने बिहार के आंकड़े नही बताये ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : The Bihar arrears are Rs. 1,73,00,000 as on 15th June, 1969.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Shri C. B. Gupta is the dominating factor in this.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Shri Randhir Singh asked why the factory should not be blacklisted and why interest should not be charged. We wish that the Haryana State Government takes some action on the lines of UP. The UP Government has framed some law whereby some interest can be charged if the arrears are there beyond a particular period.

SHRI RANDHIR SINGH : Why only interest ; penal action should be taken.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : The Haryana Government should take similar steps.

As far as production is concerned, production has gone up very much.

SHRI RANDHIR SINGH : Why do you not nationalise them ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : As to the point raised by Shri Banerjee...... (*Interruption.*)

SHRI RANDHIR SINGH : I asked four questions ; not one of them has been replied to.

MR. CHAIRMAN : He has replied to your questions.

SHRI S. M. BANERJEE : There is a serious situation in the country. The Cabinet is going to be reshuffled tomorrow.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I think, I have covered the point raised by Shri Banerjee while replying to the points made by Shastriji.

**18.10 hrs.**

*[The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 14, 1969/ Sravana 23, 1891 (Saka)].*

---

Printed at Akashdeep Printers 20, Daryaganj, Delhi-6.